मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष पर मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री करेंगे हजार करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. की मासिक समीक्षा

सौ से हजार करोड़ के एम.ओ.यू. की समीक्षा मुख्य सचिव तथा सौ से नीचे की विभागीय सचिव करेंगे

- **राइज़िंग राजस्थान में प्रदेश में निवेश के लिये हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये राज्य सरकार ने तीन स्तरीय समीक्षा व्यवस्था बनाई है।**
- **राइज़िंग राजस्थान के तहत 261 एम.ओ.यू. 1,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि के हैं। सौ से एक हजार करोड़ रूपए के एम.ओ.यू. की संख्या 1,678 है। सौ करोड़ तक के कुल 9,726 एम.ओ.यू. हुए हैं।**

जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विज़न एवं रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षिरत हुए एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है।

एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी।

राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे, जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले हैं। इसी तरह, 100 करोड़ से अधिक एवं 1 हजार करोड़ रुपये से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 तथा इनकी कुल राशि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये तक के एमओयू की संख्या 9,726 तथा इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ रूपए है।

उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षिरत हुए एमओयू की प्रगति-रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए, अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी थी। इस दिशा में त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश के विकास के लिए पूजा की

- **उन्होंने पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर व मुकुट मुखारविंद मंदिर तथा जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में पूजा-अर्चना की।**

डीग/जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को डीग के श्रीनाथ जी मन्दिर, मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस सबमें उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थीं। शर्मा डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर में मंगला आरती में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने मुकुट मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया तथा विधिवत पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर, भरतपुर रेंज आई जी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग संतोष कुमार मीणा सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके बाद, मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचे और मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर गए, जहाँ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

'भाजपा ने मेरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद देखा गया था। "इन नये वोटरों को कौन लाया था? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही खेल वे इस बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि जो लोग अब दिल्ली में नहीं रहते, जो लोग मर गये हैं, उनके नाम सूची में क्यों हों?"

केजरीवाल ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वे भाजपा के हुक्म पर अनियमितताएं नहीं करें। "मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला जायेगा, लेकिन याद रखिये, कागजात पर आप हस्ताक्षर करेंगे, और वे हस्ताक्षर बने रहेंगे।

आज या कल, सरकार बदलेगी, लेकिन फाइलें और हस्ताक्षर बने रहेंगे। नियम-कानून के अनुसार काम करना, वरना आप संकट में पड़ जायेंगे। आदेश देने वाले लोग तो बच कर निकल जायेंगे।"

आप नेता ने भागवत को सितम्बर में भी एक पत्र लिखा तथा भाजपा और उसके नेतृत्व संबंधित पांच सवाल उनसे पूछे थे। पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों, एन डी ए सरकार द्वारा अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को निशाना बनाने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाये गये थे।

अब फ्लाइट में मिलेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा। इसी के साथ ही तमाम भारतीय एयरलाइंस में एयर इंडिया पहली एयरलाइंस बन गई है, जिसने अपनी फ्लाइट में वाई-फाई सर्विस शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बताया कि शुरूआत में यह सर्विस उसके 300 से अधिक एयरक्राफ्ट के बेड़े में से कुछ ही एयरक्राफ्ट में शुरू की गई है। इनमें सभी छह ए-350, सात बोइंग-787-9 और 10 ए-321 नियो में से चुनिंदा प्लेन में। एयर इंडिया के बेड़े में अभी 10 ए-321 नियो एयरक्राफ्ट हैं।

जीवित नहीं निकल पाई 3 साल की चेतना बोरवैल से

समानांतर सुरंग खोदकर 170 फीट नीचे से 10 दिन बाद शव निकाल पाई एन.डी.आर.एफ. टीम

कोटपूतली 01 जनवरी (निस)। कोटपूतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी (3) को 170 फीट गहरे गड्ढ़े से दस दिन बाद बाहर निकाला, हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया है, जब उसे निकाला गया, तब उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। बुधवार शाम 6 बजकर 25 मिनट पर तीन साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेट कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एंबुलेंस से कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिश फेल हुईं थीं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठते रहे। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी।

- **एन.डी.आर.एफ. के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी थी। अंगुली से उसकी बॉडी के आस-पास से मिट्टी हटाई, फिर उसे बाहर निकाल सके।**
- **चेतना जब गिरी थी तब 25 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर अपने स्तर पर ही रस्सी डालकर निकालने का प्रयास किया। आशंका है हाथ ऊपर करने से चेतना फिसल कर 80 फीट गहराई तक चली गई थी।**

मृत बालिका चेतना

रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी हटाई। फिर उसे बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। पत्थर उछलकर आंखों पर आ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेटकर पत्थर तोड़ने पड़े थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी, वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते-जाते वहां फंस गई थी।

जब चेतना बोरवेल में गिरी, तब वह महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर ही उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। आशंका है कि हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसल कर करीब 80 फीट गहराई तक चली गई।

दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। बावजूद इसके, आधे घंटे बाद एसडीआरएफ-एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल लिया गया। पौने 3 घंटे बाद, यानी 5.15 बजे के करीब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर तकरीबन 150 फीट गहरे गड्ढे तक पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती, तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड किया जा सकता था।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन तथा रेस्क्यू टीमों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन में 170 फीट लंबी गहरी खुदाई, विपरीत मौसम, ऑपरेशन के दौरान बारिश होना, सुरंग के अंदर नमी, तापमान अधिक होना, जैसी अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम ने आज बच्ची को रेस्क्यू किया।

यूक्रेन ने यूरोप को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यवस्था से अक्सर अड़चन आ जाती है। हाल ही में यूरोप वैकल्पिक रूट के लिए विचार कर रहा है।

ऐसा ही एक वैकल्पिक रूट तुर्की से होकर गुजरता है जो यूक्रेन रूट की तुलना में दक्षिणी की ओर ज्यादा है। वैकल्पिक मार्ग के साथ एक समस्या यह भी है कि वे ज्यादा लम्बे हैं।

तहव्वुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था। हालांकि, कोर्ट ने भारत में किए गए हमलों के आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन माना कि वह मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहा था, और उसे भारत प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए।

केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। त्रिवेदी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आर.एस.एस. और उससे सम्बद्ध संगठनों से सेवा-भावना सीखनी चाहिए तथा अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पीछे छोड़ दीजिये।"

जलगांव में दो गुटों में हिंसा

जलगांव, 01 जनवरी। महाराष्ट्र के जलगांव के पारधी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।

प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलाढ़ी गांव में 31 दिसंबर की रात पथराव और आगजनी की घटना हुई है। कथित तौर पर मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर द्वारा हॉर्न बजाने से विवाद पैदा हुआ। इसके बाद पलाढ़ी गांव के कुछ युवक और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता चिल्लाने लगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पलाढ़ी गांव में पथराव और आगजनी की।

पुलिस ने इस घटना के बारे में कहा है कि बहस मौके पर ही खत्म हो गई थी। हालांकि, लेकिन बाद में इलाके के कुछ लोग गांव के चौराहे पर गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एक और समूह वहां पहुंचा, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

इस वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर रहेगा

- **रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों की बैठक में राजनाथ सिंह ने घोषणा की।**

नई दिल्ली, 01 जनवरी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को एक साथ कई क्षेत्रों में संचालन में सक्षम बनाना और उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू सेना बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, सुधारों और प्रगति की समीक्षा के लिए नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सिंह ने विश्वास जताया कि यह सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा, यह देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेगा, इस प्रकार 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की तैयारी करेगा। सुधारों का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण पहल को और मजबूत करना और एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित, केन्द्रित हस्तक्षेप के लिए व्यापक क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अलावा, भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं भी विकसित की जाएंगी।

एक अन्य क्षेत्र, जिसकी पहचान की गई है, वह है अधिग्रहण प्रक्रियाएं, जिन्हें तेज और मजबूत क्षमता विकास की सुविधा के लिए सरल और समय-संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सरकार रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग, अक्षमताओं को खत्म करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए प्रभावी नागरिक-सैन्य समन्वय पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी।

एक अन्य फोकस क्षेत्र, भारत को रक्षा उत्पादों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करना, ज्ञान साझा करने और संसाधन एकीकरण के लिए भारतीय उद्योगों और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के बीच अनुसंधान और विकास और साझेदारी को बढ़ावा देना भी होगा।

इस वर्ष के दौरान, पूर्व सैनिकों के कल्याण पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। सरकार उनके लिए कल्याण उपायों के अनुकूलन की दिशा में भी काम करेगी। इसके अलावा, सरकार सांस्कृतिक गौरव और विचारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में विश्वास को बढ़ावा देगी।

कश्मीर में जैश के चार सहयोगी पकड़े

श्रीनगर, 01 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा उप-जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चार आतंकवादी सहयोगियों की पहचान कर ली है।

ये हैं त्राल पाईन के मुदासिर अहमद नाइक, कुचमुल्ला के उमर नजीर शेख, त्राल पाईन के इनायत फिरदौस राथर और कौंसरबल त्राल निवासी नजीर अहमद लोन।

एक पुलिस बयान में कहा गया, गिरफ्तार किए गए सभी आतंकवादी सहयोगी त्राल और अवंतीपोरा इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेईएम के सक्रिय आतंकवादियों को रसद सहायता और हथियारों और गोला-बारूद के परिवहन में शामिल थे।

इसमें कहा गया है कि उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गईं। त्राल थाना में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

आठ पाकिस्तानियों को बीस साल की सजा सुनाई

इन्हें गुजरात तट पर 232 किलो हेरोइन के साथ 2015 में पकड़ा गया था

- **मछली पकड़ने वाली नाव के साथ पकड़े गये पाकिस्तानी नागरिक 10 साल जेल में बिता चुके हैं। उन्हें 10 साल और सजा भुगतनी होगी।**

मुंबई, 01 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 2015 में गुजरात तट से मछली पकड़ने वाली नाव पर 232 किलोग्राम हेरोइन ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश एस ई बांगर ने आठों आरोपियों को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी पाया। दोषियों की पहचान अलीबक्शा खश्केली सिंधी, मकसूद अख्तर यूसुफ मसिम, मोहम्मद बख्श नाथो, मोहम्मद अहमद मोहम्मद इनायत, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला गगवानी, मोहम्मद यूनुस हाजी मोहम्मद सुमार सिंधी, मोहम्मद गुलहसन मौलाबख्श बलूच सिंधी और गुलहसन मोहम्मद सिद्दीक सिंधी के रूप में हुई है। सभी दोषी पाकिस्तानी नागरिक हैं।

इन सभी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय से ये लोग जेल में बंद हैं, इसलिए उस अवधि को ध्यान में रखा जाएगा और अब उन्हें जेल में और दस साल बिताने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में आरोपियों ने मछुआरे होने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी नावों में हेरोइन के पैकेट क्यों थे। वहीं, इन लोगों के पास तीन सैटेलाइट फोन थे, जिनका इस्तेमाल भारत या पाकिस्तान के नागरिकों को करने की अनुमति नहीं है और नाव पर जीपीएस दिशासूचक चार्ट पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि वे भारत जा रहे थे। अदालत ने इस आधार पर मामले में बरी करने की बचाव पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया कि मुंबई पुलिस के पास इस मामले को संभालने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जब्ती अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जिस क्षेत्र में गिरफ़्तारी हुई, वह समुद्री अधिनियम और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

केन्द्र ने फसल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कम होगी।सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए किया है। सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का बोझ किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है

भारत-पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपी

- **वर्ष 2008 के समझौते के अनुसार, हर वर्ष जनवरी व जुलाई में इन सूचियों का आदान-प्रदान होता है।**

नयी दिल्ली, 01 जनवरी। भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को एक-दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों-नागरिकों और मछुआरों- की सूचियों तथा एक-दूसरे के क्षेत्र में परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं की सूचियों का आदान-प्रदान किया। कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान, राजनयिक चैनलों के माध्यम से और एक साथ नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में, राजनयिक संपर्क पर 2008 के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को किया जाता है।

वहीं, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूचियों का आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु स्थापना और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया गया है, जिस पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी 1991 को यह लागू हुआ था। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान पहली जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान एक जनवरी 1992 को हुआ था।

एक सरकारी बयान के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में बंद 381 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं।

बयान में कहा गया है कि इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 49 नागरिक कैदियों और 217 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नौकाओं तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आव्हान किया है।

पाकिस्तान से उन 183 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने को कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा, पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 18 नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल राजनयिक संपर्क प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और अब तक उन्हें राजनयिक संपर्क प्रदान नहीं की गई है।

पाकिस्तान से सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले नागरिक कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जब तक कि उनकी रिहाई और भारत में वापसी नहीं हो जाती।

भारत एवं पाकिस्तान एक-दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मामलों सहित, सभी मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बजट 2025-26 में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम करने के लिए फेसलैस एसैसमैंट सिस्टम लाना शामिल हैं, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। इन परिवर्तनों से व्यवसायों में भरोसा बढ़ेगा।

भारत में एफ.डी.आई. का प्रवाह हालिया वर्षों में लगातार बढ़ा है और आगामी बजट में ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि प्रवाह की ये गति कायम रहे। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी और यातायात का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा।

इसके अलावा, सरकार अक्षय ऊर्जा, ई-वाहन व अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे सकती है। भारत के तेजी से बढ़ते खुदरा बाज़ार और ई-कॉमर्स सैक्टर में एफ.डी.आई. के नियमों में छूट दी जा सकती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।

टैक्नॉलजी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के एफ.डी.आई. के प्रमुख क्षेत्र बने रहने की संभावना है। सरकार अतिरिक्त कर लाभ या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का प्रस्ताव दे सकती है, आर्टिफिशियल इन्टैलीजैंस, ब्लॉक चेन और क्लाउड कम्प्यूटिंग में। इन कदमों से भारत को तकनीकी नवाचार में ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिलेगी।

रक्षा क्षेत्र, एयरोस्पेस और ई-कॉमर्स में एफ.डी.आई. की मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, इंटैलेक्युअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटैक्शन को मजबूत बनाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाएगा, खासकर टैक्नॉलजी क्षेत्र में।

कायदे-कानूनों का सरलीकरण करने और डिजिटल शासन से सरकार को बिज़नैस वातावरण और बेहतर बनने की उम्मीद है और इससे एक पारदर्शी और प्रभावी इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसमें नौकरशाही बाधाएं कम होंगी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908